There has been a wave of setting up chemical industrial zones on the banks of these west-flowing, diversity-rich rivers. Chemical industries have been set up on the Patalganga river (Patalganga Rasayani Industrial Area).

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाएं

*151. **श्री हरनाथ सिंह यादव**: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, वर्ष-वार, इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने व्यक्ति मारे गए; और

(ग) इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं के होने के क्या कारण हैं और सरकार ने इन्हें रोकने के लिए क्या-क्या उपाए किए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी): (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने और उनका अनुरक्षण करने का अधिदेश प्राप्त है। नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे एनएचएआई या इस मंत्रालय द्वारा निर्मित और प्रबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

जहाँ तक सड़क सुरक्षा का संबंध है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में जागरूकता बढ़ाने, सड़क सुरक्षा सूचना डाटा बेस तैयार करने, कुशल परिवहन के अनुप्रयोग सहित सुरक्षित सड़क संरचना को बढ़ावा देने, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन जैसे विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मसलों से निपटने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति बनाई है, जो शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित है। इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में उस जिले के माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित की है।

उपर्युक्त के अलावा, सड़क सुरक्षा का संवर्धन करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा की गयी पहलों को निम्नवत् सूचीबद्ध किया गया है:

(i) जागरूकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान।

(ii) गुड स्मारिटन की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

(iii) राज्यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

(iv) स्वचालित प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए 22 परीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र की संस्वीकृति।

(v) राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, जिसका नाम „सुखद यात्रा 1033%है। इससे राजमार्ग प्रयोक्ता दुर्घटनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढ़ों और अन्य सुरक्षा खतरों की शिकायत कर सकते हैं।

(vi) जागरूकता फैलाने तथा सड़क सुरक्षा उपाय को कारगर बनाने के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

(vii) सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन का एक अनिवार्य भाग बनाया गया है।

(viii) राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में परिवर्तन के लिए न्यूनतम अपेक्षा 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है।

(ix) वाहनों के सुरक्षा मानकों में सुधार किए गए हैं।

(x) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(xi) मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभिनिर्धारित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण हेतु विस्तृत प्राक्कलन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति प्रदान की है।

(xii) दिव्यांजनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी पैदल यात्री सुविधा दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को भी जारी कर दिए गए हैं।

(xiii) भारतीय राजमार्ग अभियंता अकदामी (आईएएचई) ने सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है और 42 संपरीक्षकों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

(xiv) राजमार्ग पर चलने वाले ट्रक/बस चालकों के लिए नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं और चश्मों का वितरण किया जाता है।

(xv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फाइल संख्या आरडब्लयू/एनएच-33044/309/2016 / एस एंड आर दिनांकित 06-04-2017 और 01-06-2017 के परिपत्र के माध्यम से शराब की दुकानें हटाई गई हैं।

Accidents on Noida-Agra Yamuna Expressway

†*151. SHRI HARNATH SINGH YADAV: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

†Original notice of the question was received in Hindi.

(a) the number of road accidents on Noida-Agra Yamuna Expressway during the last three years;

(b) the number of persons injured and killed in these accidents, year-wise details thereof; and

(c) the reasons for such a large number of accidents and measures taken by Government to prevent them?

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Ministry of Road Transport and Highways is mandated with the task of constructing and maintaining National Highways in the Country. Noida-Agra Yamuna Expressway is not a National Highway constructed and managed by NHAI or this Ministry.

With regard to Road Safety, the National Road Safety Policy outlines various policy measures such as promoting awareness, establishing road safety information data base, encouraging safer road infrastructure including application of intelligent transport, enforcement of safety laws. The Ministry has formulated a multi-pronged strategy to address the issue of road safety based on Education, Engineering (both of roads and vehicles), Enforcement and Emergency Care. Further, the Ministry of Road Transport & Highways has constituted a District Road Safety Committee in each district of the country to promote awareness amongst road users under the chairmanship of HonÊble Member of Parliament (Lok Sabha) from the district.

In addition to the above, the initiatives of the Ministry to promote road safety are listed as below:

(i) Advocacy/Publicity campaign on road safety through the electronic media and print media to create awareness.

(ii) Issue of Guidelines for protection of Good Samaritans.

(iii) Setting up of model driving training Institutes in States.

(iv) Sanction of 22 Inspection and certification Centres for testing the fitness of the commercial vehicles through an automated system

(v) Launch of mobile app for highway users *i.e.* „Sukhad Yatra 1033‰ which enables highways users to report potholes and other safety hazards on National Highways including accidents.

(vi) Observance of Road Safety Week every calendar year for spreading awareness and strengthening road safety.

(vii) Road safety has been made an integral part of road design at planning stage.

(viii) The threshold for four laning of national highway has been reduced from 15,000 Passenger Car Units (PCUs) to 10,000 PCUs.

(ix) Safety standards for automobiles have been improved.

(x) High priority has been accorded to identification and rectification of black spots (accident prone spots) on national highways.

(xi) Ministry has delegated powers to Regional Officers of MORTH for technical approval to the detailed estimates for rectification of identified Road Accident black spots for expediting the rectification process to ensure safety of road users.

(xii) Guidelines for pedestrian facilities on National Highways for persons with disabilities have also been issued to all States / UTs.

(xiii) Certification Course for Road Safety Auditors has been commenced in Indian Academy of Highway Engineers (IAHE) and 42 Auditors are certified.

(xiv) Free Eye Check-up Camp and distribution of eye glasses is conducted for truck/ bus drivers operating on NH.

(xv) Removal of Liquor Shops as per directions of HonÊble Supreme Court *vide* circular of F. No. RW/NH-33044/309/2016/S&R dated 06-04-2017 and 01-06-2017.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*)

श्री हरनाथ सिंह यादव: माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे एनएचआई या इस मंत्रालय द्वारा निर्मित और प्रबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: This is not the way. ...*(Interruptions)*... He is not well. I am told that he has come from the hospital. ...*(Interruptions)*... I appreciate his spirit. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

श्री हरनाथ सिंह यादव: महोदय, कैसा संयोग है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर आज ही आगरा के पास प्रात:काल 4.30 बजे एक बस दुर्घटना में लगभग 29 लोगों की मृत्यु हो गई। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप लोग अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए और बैठिए। This is not the way. I will never get work done underpressure. ...*(Interruptions)*...

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, आत प्रात: ही आगरा के पास हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। ...(**व्यवधान**)... No point of order. ...*(Interruptions)*... You are not in order. ...*(Interruptions)*... How can you raise a point of order? ...*(Interruptions)*...

श्री हरनाथ सिंह यादव: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृत अथवा घायल व्यक्तियों के परिवारजनों को राजमार्ग प्राधिकरण अथवा पथ-कर संग्रह कंपनियों अथवा मोटर अभियोजन कंपनियों के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और यदि नहीं, तो क्या माननीय मंत्री जी मृत अथवा घायल व्यक्तियों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान करने पर विचार करेंगे?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने यमुना एक्सप्रेसवे पर जो सवाल पूछा है, मैं उस संबंध में बताना चाहता हूं कि यह बात सच है, आज भी वहां एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और दुर्भाग्यवश 21 या 22 लोगों की वहां मृत्यु भी हुई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदय, 29 लोग मरे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please correct it.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI Sir, I will correct it.

महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि यह हाइवे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, इसलिए इसका भारत सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है और इस हाइवे का कंट्रोल भी नोएडा अथॉरिटी के पास है। चूंकि यह question मेरे Department को mark किया गया है, इसलिए मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। मेरी नोएडा अथॉरिटी के लोगों से आज बातचीज हुई है। यह सीमेंट और कॉन्क्रीट का हाइवे है। इस पर जो accidents हुए हैं, उनके details लिए गए हैं। उसके अनुसार वर्ष 2016 में 1525 accidents हुए थे, जिनमें 133 लोग मारे गए थे, वर्ष 2017 में करीब 146 लोगों की मृत्यु हुई है एवं वर्ष 2018 में 111 लोगों की मृत्यु हुई। आज जो accident हुआ है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने एक committee भी constitute की है।

महोदय, रोड़ सेफ्टी के लिए जो दो-तीन बातें ध्यान में आई हैं, उस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो टायर बनते हैं, उनके standards और जो International standards हैं, वे क्या हैं, इस बारे में अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं थी। मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका और बाकी पाश्चात्य देशों में टायर बनाते समय रबर के साथ सिलिका डाला जाता है, जिसके कारण temperature बढ़ने और टायर के गर्म होने के बाद जब वह फटता है, तो उन देशों में उसकी complaints कम होती हैं। दूसरी बात यह है कि टायरों में साधारण हवा के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरनी चाहिए, जिससे कि टायर ठंडा रहता है और टायर फटने की घटनाएं कम होती हैं।

MR. CHAIRMAN: Question has to be short...*(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: Sir, we are staging a walk-out in protest. ...*(Interruptions)*...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

श्री नितिन जयराम गडकरी: महोदय, हम इन दोनों बातों को mandatory करने के बारे में सोच रहे हैं। इस रोड पर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनके कारणों का निष्कर्ष निकाल कर हमने उत्तर प्रदेश सरकार से भी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है?

श्री हरनाथ सिंह यादव: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या देश के सभी प्रकार के मार्गों के वातावरण को शुद्ध एवं सुरम्य बनाने के लिए मार्गों के दोनों ओर लम्बे झाड़दार और छायादार वृक्ष लगाने की सरकार की कोई कार्य-योजना है, यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है और यदि नहीं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस दिशा में विचार करेंगे?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सभापति जी, पूरे राष्ट्रीय महामार्ग की संख्या 1 लाख, 36 हजार किलोमीटर हुई है और इस बार हमारी तरफ से, जितनी हमारे देश की आबादी है, उसके हिसाब से हमने 125 करोड़ वृक्ष लगाने की योजना तैयार की है। MSME के नाम से जो दूसरा विभाग है, उनको हिदायत है कि वे small-scale industries में कम से कम पांच वृक्ष लगाएं और medium-scale में पचास वृक्ष लगाएं। इन दोनों योजनाओं पर महाराष्ट्र सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है। आने वाले Parliament Session के बाद - महाराष्ट्र सरकार के Forest Minister और जो काम करने वाले अधिकारी हैं, उन्होंने ई-टैग किया है और वे इस साल 36 करोड़ वृक्ष लगा रहे हैं। हम लोग उस योजना की आर्क पर काम करके इस चीज को करने की जरूर कोशिश करेंगे। मैं समग्र गृह से आह्वान करूंगा कि educational institutions, social organizations आदि के जो लोग भी इसमें शरीक होंगे, हम उन्हें इसमें शरीक करने की कोशिश करेंगे।

प्रो. राम गोपाल यादव: सभापति जी, यद्यपि यह प्रश्न यमुना एक्सप्रेसवे से संबंधित है, जो कि यमुना विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, लेकिन जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें चाहे वह यमुना एक्सप्रेसवे हो, national highways हों, National Highways Authority of India के अंतर्गत आने वाले highways हों, उनमें मुख्य कारण over-speeding, ज्यादा सवारियों को भरना और ड्राइवर्स का शराब पीकर drive करना है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इसको राज्यों पर मत डालिये। National highways पर जो accidents होते हैं, वे ज्यादातर इन्हीं कारणों से होते हैं। जो रात में accidents होते हैं, उनका एक कारण यह भी होता है कि वे शराब पीकर गाड़ी चला रहे होते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वे medically fit drivers हैं या नहीं हैं, कैमरे लगे हुए हैं लेकिन उन पर over-speeding का जुर्माना लगता है या नहीं लगता है और ज्यादा सवारियां भरने पर यदि आप checking की व्यवस्था नहीं कर सकते तो क्या आप राज्य सरकारों को इसका निर्देश देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री सभापति: मंत्री जी, उन्होंने तीन general बिंदु रेज़ किए हैं।

श्री नितिन जयराम गडकरी: सभापति जी, इसके automobile engineering के कारण होते हैं, road engineering के कारण होते हैं, driving license के कारण होते हैं और शराब पीकर गाड़ी चलाने के भी कारण होते हैं। इसने इसकी पूरी मीमांसा की है। हमने principally 14 हज़ार करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है जिसमें यह विचार रखा है कि black spot को identify करके इन कमियों को कैसे कम करें। हमने automobile engineering में भी बहुत से सुधार किए हैं। अभी एक ऐसी latest technology आई है, जिसमें यह है कि अगर ड्राइवर ने दारू पी है तो machine चालू ही

नहीं होगी, यदि belt नहीं बांधी है तो police headquarters में bell बज जाएगी कि उस गाड़ी का ये नंबर है, जिसने बेल्ट नहीं लगाई है। हम लोग इसमें सभी sophisticated चीज़ों को कर रहे हैं, परंतु मैं इस बहाने आपसे और सदन से अनुरोध करूंगा कि इस देश में अभी जो satistics हैं, वे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं बताना चाहूंगा कि केवल तमिलनाडु में 15 परसेंट एक्सिडेंट्स कम हुए हैं, इस मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है और इसके 15 परसेंट मामले बढ़े भी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामले तमिलनाडु में 29 परसेंट कम हुए हैं। हम तमिलनाडु के मॉडल पर काम कर रहे हैं और हमने ठीक काम किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं एक साल तक आपके पास इसका बिल लेकर आता रहा और आपसे बार-बार कहता था कि लोग कर रहे हैं, driving license की प्रॉब्लम है, अन्य पचासों बाते हैं, आप मेरा बिल पास कीजिए। ...**(व्यवधान)**... यह बिल कोई सरकार का बिल नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: ठीक है।

श्री नितिन जयराम गडकरी: मैंने हाउस में बहुत बार यह चीज़ उठाई। ...**(व्यवधान)**... अब मैं आपसे गंभीरता से इसका आह्वान करता हूं कि यह कोई politicalised subject नहीं है। ...**(व्यवधान)**... मेरा भी एक्सिडेंट हुआ था, मैं भी मरते-मरते बचा हूं। ...**(व्यवधान)**... रेड लाइट कारण है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इनमें लगभग 30 परसेंट bogus license हैं। हम कुछ नहीं कर पाते, हमारे पास कोई अधिकार नहीं हैं, इसलिए जो Road Safety Bill है, आप उसको जैसे ही मंजूर करेंगे, वैसे ही हमें कार्यवाही करने का अधिकार मिलेगा, इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उसको पास करने में सहयोग कीजिए।

PROF. RAM GOPAL YADAV: I agree with you.

MR. CHAIRMAN: Both have agreed. It is good.

श्री शिव प्रताप शुक्ल: माननीय सभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में एक बात को कहा है कि चूंकि concrete road cemented हैं और tyre के फटने की वजह से अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। यह सही है कि आपने जो कहा है कि जिस speed से गाड़ियां जाती हैं - अगर हम लोग यहां से ट्रेन से जाते हैं, तो लखनऊ तक पहुंचने में नौ घंटे लगते हैं, तो ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री शिव प्रताप शुक्ल: मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। वहां पहुंचने में नौ घंटे लगते हैं, लेकिन ये जो buses जाती हैं, जो private buses हैं, वे पांच घंटे में लखनऊ पहुंचाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इन buses की और जो लोग कार से जाते हैं, उनकी speed की कोई limit बांधने का काम करेंगे?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सभापति महोदय, world में जो UK और बाकी standards हैं, उनके हिसाब से हमने बस की बॉडी का निर्माण करने के लिए 2017 से एक योजना का क्रियान्वयन किया है। स्पीड कम करना, यह इसका उपाय नहीं है। देश में मुम्बई और पुणे के बीच पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। अब हम दिल्ली से मुम्बई एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। इसलिए स्पीड कम करने

की बजाय road safety measures के आधार पर हम technology के जरिए बसों में ऐसा सुधार करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वे स्पीड से जा रही हैं, उनमें control करने का सिस्टम भी अच्छा रहेगा और उनसे accidents नहीं होंगे। इसकी चिंता करते हुए हम इस technical सुधार को महत्व दे रहे हैं। हमने 2017 से इसको लागू किया है। नए मॉडल में यह problem नहीं है। कल जो accident हुआ, वह 2017 का अशोक लेलैंड का मॉडल था। जब इसमें धीरे-धीरे technical सुधार हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि problem नहीं आएगी।

MR. CHAIRMAN: Dr. T. Subbarami Reddy. Are you not a part of any such activity?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, the hon. Minister has given various measures to control accidents. We appreciate that; I am very happy. There are two issues; setting up of model driving training Institutes in States, and, sanction of 22 Inspection and certification Centres for testing the fitness of the commercial vehicles through an automated system. I would like to know from the hon. Minister: With regard to these two things, to what extent have you achieved and what is the progress?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, देश में 25 लाख ड्राइवर्स की कमी है। ड्राइवर्स की training के लिए हमने 65 Driving Training Schools दिए हैं। इसमें हमने कहा कि Driving Training Institute को लाइसेंस देने का अधिकार भी हो और fitness certificate देने का अधिकार भी हो, इसके ऊपर अभी तमिलनाडु हाई कोर्ट ने एक stay दिया है। आज ही मुझे उस stay की जानकारी मिली है। हम लोग निश्चित रूप से देश में बड़े पैमाने पर driving की training के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार की योजना के आधार पर हम करीब 850 Driving Training Centres खोल रहे हैं। अगर ड्राइवर्स प्रशिक्षित हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें कमी आ सकती है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप इसमें जरूर सहयोग करें।

श्री सभापति: क्वेश्चन नं. 152 Questioner यहाँ उपस्थित नहीं है। क्या इसके ऊपर कोई माननीय सदस्य supplementary पूछना चाहते हैं?

*152. *[The questioner was absent].*

Ground water pollution

*152. SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether indiscriminate use of chemicals and fertilizers during the last three years is a major cause of rapidly increasing ground water pollution in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken by Government to check ground water pollution during the last three years?